



हिन्दी दैनिक

नवयुग समाचार

बहाइय से प्रकाशित

एक सामाजिक दर्पण

लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, कानपुर, कन्नौज, फरुखाबाद, गोरखपुर, अंबेडकरनगर, म.प्र., बिहार में प्रसारित

गिरिराज सिंह ने संसद परिसर में सोनिया और सोरेस का पोस्टर लहराया
नई दिल्ली

संसद का शीतकालीन सत्र की शुरूआत से सदन में अडानी और जर्ज सोरेस का पोस्टर लहराये का दीरं जारी है। बुधवार को कांग्रेस सांसदों ने सत्ता पक्ष के नेताओं को तिरंगा और गुलाब देकर अपना प्रदर्शन किया था। इससे पहले लोकसभा में विधायकों ने नेता राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी अडानी की फोटो छोड़ दी थीं लेकर परिसर पहुंचे थे।

अब बीजेपी ने सोरेस मुद्दे को लेकर संसद में प्रदर्शन शुरू किया है। बीजेपी संसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संसद परिसर में सोनिया और सोरेस का पोस्टर लहराया है। वहाँ, विपक्ष की तरफ से भी संसद परिसर में प्रोटेस्ट हो रहा है। विपक्षी सांसदों ने देश बिकने नहीं देंगे नारे के साथ संसद में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने 9 दिसंबर को राहुल गांधी पर भारत की कथित तरफ पर अस्थिर करने के लिए जर्ज सोरेस जैसी अंतरराष्ट्रीय ताकतों के साथ मिलीभांत का अरोप लगाया था।

फिलिस्तीनी राजदूत प्रियंका गांधी से मिले, वायनाड सांसद बनने पर दी बधाई
नई दिल्ली

भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अबेद एलराजेम अब जारी ने बुधवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। उन्होंने प्रियंका को बायनाड लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने पर बधाई दी। इस मुलाकात में प्रियंका गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए फिलिस्तीनी लोगों के संघर्ष और अपने समर्थन देने की उम्मीद की।

उन्होंने कहा कि वह बचपन से ही

फिलिस्तीनी हिंतों के लिए जी रही हैं

और इसके न्याय में विश्वास करती हैं।

इसके अलावा उन्होंने बचपन में

फिलिस्तीनी नेता यासिर अबाकत की

भारत यात्रा के दौरान कई बार पूर्व

पीएम राहुल गांधी, राजीव गांधी से

मुलाकात की है।

इस दौरान प्रियंका ने गाजा में चल

रही इजराइली सैन्य कार्रवाईयों की निंदा

की और क्षेत्र में विनाश और तबाही के

लिए गहरा दुख व्यक्त किया। प्रियंका

गांधी ने यात्रा की दिशा में भारत

की भूमिका के लाभता की जाक की।

उन्होंने गाजा में भारत के प्रशाव के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के निरंतर

समर्थन पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

महत्व पर जो दोहे हुए फिलिस्तीनी

अधिकारों के लिए भारत के

संपादकीय

अरावली की बलि

उस खबर ने हर संवेदनशील और जागरूक व्यक्ति को उद्घेलित किया है कि हरियाणा के नूह के पास 22 अरब रुपये की मत के पहाड़ को खनन माफिया चट कर गया। निस्सदैह, यह प्रेरणा करने वाल घटनाक्रम नूह जिले में राजस्थान सीमा पर स्थित पहाड़ से जुड़ा है जो अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। विडंबना यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम तंत्र की काहिलो व सत्ताधीशों की गैरजिम्मेदारी से पनपा है। खनन विभाग की रिपोर्ट बताती है कि उपमंडल फिरोजपुर झिरका के कुछ इलाकों में खनन माफिया ने इस कृत्य को अंजाम दिया। कैसी विडंबना है कि गैर कानूनी तरीके से धन अर्जित करने की दबंगों की लिप्सा हमारे पर्यावरण व लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने से भी गुरेज नहीं करती। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम यह भी है कि अवैध खनन माफिया से टक्कर लेने वाले कई अधिकारियों को तबादले के रूप में खमियाज भी भुगतना पड़ा है। नागरिक संगठनों की उदासीनता भी उन खनन माफियाओं का हौसला बढ़ाती है, जो सत्ता के गलियारों में खासगंথ रखते हैं। निश्चित रूप से हमारे पारिस्थितिकीय तंत्र के सुतुलन में निर्णयिक भूमिका निभाने वाली इन पहाड़ियों को आज पुनर्जीवित करने की जरूरत है। पर्यावरण पुनर्स्थापना हेतु भूमिक्षण और मरुस्थलीकरण से निवटने के लिये बाकायदा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में ग्यारह लाख मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए, इस चौदह सौ किलोमीटर लंबे और पांच किलोमीटर चौड़े हरित गलियारे को बनाने का लक्ष्य है कि अरावली पहाड़ियों की पारिस्थितिकीय जीवन शक्ति को फिर से बहाल किया जा सके। एक समय था कि ये पहाड़ियां जंगल, बन्दर जीवों, जलचरों और प्राकृतिक जल निकासी के जरिये एक समृद्ध पारिस्थितिकीय तंत्र बनाती थीं। लेकिन दुर्भाग्य से अब अरावली पर्वतीय श्रंखला देश की सबसे खराब स्थितियों के लिये जानी जाती है।

अंतर्गत हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में खारह लाख मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए, इस चौदह सौ किलोमीटर लंबे और पांच किलोमीटर चौड़े हरित गलियारे को बनाने का लक्ष्य है कि अरावली पहाड़ियों की पारिस्थितिकीय जीवन शक्ति को फिर से बहाल किया जा सके। एक समय था कि ये पहाड़ियां जंगल, वन्य जीवों, जलचरों और प्राकृतिक जल निकासी के जरिये एक समृद्ध पारिस्थितिकीय तंत्र बनाती थी। लेकिन दुर्भाग्य से अब अरावली पर्वत शृंखला देश की सबसे खराब स्थितियों के लिये जानी जाती है। इस दिशा में सत्तार्थीयों की उदासीनता और नियामक संस्थाओं की लापरवाही से हरियाणा में यह स्थिति खासी शोचनीय है। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि अरावली पर्वत शृंखला की तीस से अधिक पहाड़ियों पहले ही लुप्तप्राय हो चुकी हैं। खासकर हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों से लगते इलाकों में। निरंतर होते शहरों के विस्तार ने हेरे-भेरे परिवहनों को कंक्रीट के जंगलों में तब्दील कर दिया है। जिसके चलते पूरे इलाके का पारिस्थितिकीय संतुलन बाधित हुआ है। सदियों में विकसित हुई दुर्लभ्य। माधवे, धवले पक्षे सिंह जीवे इनोश्वरे। तुलाराशौ क्षपानाथे स्वातिथे पूर्णिमा तिथौ। व्यतिपाते तु सप्तापाते चंद्रवासर संयुते। । एजेनशन तमायोगः स्थानान्मुक्ति फलप्रदा। । उक्त संदर्भ समुद्र मंथन से है। जब देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन किया गया, मंथन से अमृत सहित चौदह दिव्य रत्नों की प्राप्ति, अमृत पर अधिकार के लिये देव-दानवों में संघर्ष और संघर्ष में भारत के चार प्रमुख तीर्थों में अमृत बिन्दु का छलक पड़ना। अमृत बिन्दु पतन से चारों तीर्थ स्थान अमर और पवित्र हो गये। यहां की पवित्र नदियां भी अमृतमयी हो गई हैं।

वन संपदा व जाव-जतुआ के अधिवास अब विलुप्त होने के कगार पर हैं। निस्सदेह, इस कथित विकास की कीमत हमें लंबे समय तक चुकानी होगी। जिसके अंतर्गत स्वदेशी वृक्षों की अनेक महत्वपूर्ण किस्में व दुर्लभ वन्य जीवों की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर जा पहुंची हैं। साथ ही अनेक महत्वपूर्ण भूजल पुनर्भरण क्षेत्र सूख गए हैं। उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब की हरित पहल से प्रेरित होकर ही ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को इस विनाशकारी अतिक्रमण के रोकने के लिये लाया गया था। स्वदेशी वन संपदा को सामुदायिक जुड़ाव के जरिये संरक्षित करने की योजना थी। इसके अंतर्गत 35000 हेक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना भी मकसद था निस्सदेह, इस पर्यावरणीय संकट से निबटने के लिये पर्वत शृंखल के निकटवर्ती राज्यों में सहयोगात्मक प्रयास जरूरी हैं। उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक भी वनीकरण, जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण जैसी पहलों के लिये वित्त पोषण करके अरावली परियोजना के संबल दे रहा है।

(ਪਿਤਾਨ-ਮਨਨ)

इरपर का दास्ता

है। देवदूत के हाथ में एक सूची थी। उसने कहा, यह उन लोगों का सूची है, जो प्रभु से प्रेम करते हैं। संत ने कहा, मैं भी प्रभु से प्रेम करता हूँ। मेरा नाम तो इसमें अवश्य होगा। देवदूत बोला, नहीं, इसमें आप का नाम नहीं है। संत उदास हो गए। फिर उन्होंने पूछा, इसमें मेरा नाम क्यों नहीं है? मैं ईश्वर से ही प्रेम नहीं करता बल्कि गरीबों से भी प्रेम करता हूँ। मैं अपना अधिकतर समय निर्धनों की सेवा में लगाता हूँ। उसके बाद जी समय बचता है उसमें प्रभु का स्मरण करता हूँ। तभी संत की आँख खुल गई। दिन में वह स्वप्न को याद कर उदास थे। एक शिष्य ने उदासी का कारण पूछा तो संत ने स्वप्न की बात बताई और कहा, लगता है सेवा करने में कहीं कोई कमी रह गई है। दूसरे दिन संत ने फिर वही स्वप्न देखा। वही देवदूत फिर उनके सामने खड़ा था। इस बार भी उसके हाथ में कागज था। संत ने बेरुखी से कहा, अब क्यों आए हो मेरे पास? मुझे प्रभु से कुछ नहीं चाहिए। देवदूत ने कहा, आपको प्रभु से कुछ नहीं चाहिए, लिकिन प्रभु का तो आप पर भरोसा है। इस बार मेरे हाथ में दूसरी सूची है। संत ने कहा, तुम उनके पास जाओ जिनके नाम इस सूची में हैं। मेरे पास क्यों आए हो?

देने के लिए तेलंगाना की राजधानी हैंदराबाद स्थित फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैंबर एंड कॉर्पस में दो दिवसीय राष्ट्रीय किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। जिसमें कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से व्यावहारिक चर्चा करने के लिए देश भर से किसान नेता, कृषि वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रगतिशील किसान एक मंच पर एकत्रित हुए। सिफा के संस्थापक और मुख्य सलाहकार पी. चंगल रेड्डी के अनुसार भारत में खाद्य सुरक्षा और इस क्षेत्र में वैश्विक निर्यातक बनने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति के अवसर हैं। आज जलवायु परिवर्तन को ध्यान रखकर खेती करने और युवा प्रतिभाओं को खेती की ओर आकर्षित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण और कृषि निर्यात के क्षेत्रों में भी अपार अवसरों की उपलब्धता है, जिन्हें सही ढंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

भारतीय किसान संघ परिसंघ के मौजूदा चेयरमैन रघुनाथ दादा पाटील ने देश भर से आए किसान नेताओं और प्रतिनिधियों से कहा कि इसमें कोई शक नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था की ओर किसान इसकी जीवनविधि किसान सबसे बड़ा उत्पाद उपभोक्ता दोनों है। किसान वैज्ञानिकों के बीच अंतर विद्युत लिए 'प्रयोगशाला' को जोड़ने के प्रयासों की भूमिका आवश्यकता है ताकि वह इसका किया जा सके कि अत अनुसंधान जीवीनी स्तर तक कृषि में विविधता लाने के लिए किसानों को गेहूं और धान पारंपरिक फसलों के समान अनुसंधान जीवीनी स्तर तक कृषि के लिए नीतिगत पहल योजनाओं, निर्यात नीति पर चर्चा की गई। पीजेट ने एसोसिएशन के चेयरमैन बालियान ने कहा कि भारत ने 2018 में एसेसिल वैकल्पिक एकट की पावर को एकट करते हुए चीनी का न्यूनतम मूल्य तय किया था। ठीक उसी केंद्र सरकार 23 फसलों पर एसेसिल कमोडिटी एकट की

कृषि विकास के लिए जैसी सरकारी और नियंत्रित व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। इसके अलावा व्यापक व्यवस्था का विकास करने की ज़रूरत है। इसके लिए सरकारी और नियंत्रित व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। इसके अलावा व्यापक व्यवस्था का विकास करने की ज़रूरत है।

जीवन और
प्रकार की रक्षा
पूर्व, नीलगाय
र हमला करने
लिए मुख्य
अपनी शक्तियों
सकता है, जो
को एक निश्चित
पर जानवरों को
ना सकता है।
गोर्गोइजेशन से
पशेषज्ञ गणधर्म
ताया कि किस
उनके सहकर्मी
चेंगल रेड़ी के
और लगातार
बाद हाल ही
ने हाई टेंशन
लिए मानक
की की है। टाकर
मूल्य का 200
दिया जाएगा।
ड-लेवल लेग
एक अतिरिक्त
र स्थान टाकर
में जाना जाता
अनुसार, जिला
नस्टट या डिप्टी
वजे के लिए

अंतिम अधिकार दिया जाएगा।
मुआवजे पर निर्णय लेने से पहले,
हम अनुरोध करेंगे कि जिला
कलेक्टर नवीनतम (14 जून
2024 को बिजली मंत्रालय के
दिशा-निर्देश) दिशा-निर्देशों पर
विचार करें। दूसरे दिन के अंतिम
सत्र में सिफा के मुख्य सलाहकार
पी. चेंगल रेड़ी के मार्गदर्शन में
सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा सिफा की
नई संगठन कार्यकारी समिति और
प्रशासनिक टीम का गठन किया
गया। महाराष्ट्र से रघुनाथ दादा
पाटील को चेयरमैन और गुजरात के
विधिन चंद्र पटेल को राष्ट्रीय
अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई वहीं
झारखंड दुमका से ताल्लुक रखने
वाली सुष्मिता सोरेन, उत्तर प्रदेश से
अशोक बालियान और तेलंगाना से
मारा गंगा रेड़ी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
का पद भार सौंपा गया। राष्ट्रीय
किसान सम्मेलन में भागीदारी
सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक से
शकर नारायण रेड़ी, गुजरात से
विधिन भाई पटेल, तमिलनाडु से
आर व्ही गिरी, आंध्र प्रदेश से कोटी
रेड़ी नरेंद्र बाबू, तेलंगाना से गोपाळ
रेड़ी, निमू वसंता, माधव रेड़ी,
सोमशेखर राव, उत्तर प्रदेश से

महाकुंभ पर्व पर विशेषः प्रयागराज का महाकुंभ सामाजिक समरसता और एकता का महासूग्र

-सुरेश सिंह वैस शाश्वत

धर्मों और संप्रदायों में रने वाला हमारा यह देश नेक पर्व, उत्सव और मेले होते हैं, इसलिए यह रक्षात वार और नौ त्यौहार पर्वों और उत्सवों से त्याग, ना, परोपकार, धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना के हैं। ऐसे ही सनातनधर्मियों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव, या कह सकते हैं जो विश्व का सबसे बड़ा जा सकता है। यह महापर्व और कहां मनाया जाता है, वार को पुराणों में उल्लेखित यों से समझा जा सकता है। ली तीर्थवर, देवानामपि, अधवे, ध्वले पक्षे सिंह जीव तुलाराशौ क्षपानाथे स्वातिथे त्रौ। व्यातिपाते तु सम्प्राप्ते अंयुते। एजेनशन महायोगः फलप्रदा। । उक्त संदर्भ से है। जब देव दानवों द्वारा किया गया, मर्थन से अमृत इह दिव्य रत्नों की प्राप्ति, अधिकार के लिये देव-धर्ष और संर्ध में भारत के तीर्थों में अमृत बिन्दु का ना। अमृत बिन्दु पतन से स्थान अमर और पवित्र हो की पवित्र नदियां भी हो गई हैं।

विष्णु द्वारे तीरथराजे
बन्त्यां गोदावरी तटे।
सुधा बिन्दु विनिक्षेपात्
कुम्भपर्वति-विश्रुतम् ॥ १
अर्थात् अमृत बिंदु पतन से पृथ्वी पर
चार कुंभ पर्व हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन
और नासिक में आयोजित होते हैं
जिसमें हरिद्वार का कुंभ पर्व कुंभ राशि
के गुरु, मेष के सूर्य में वैशाख मास में
आयोजित होता है। वहीं प्रयाग
(इलाहाबाद) का कुंभ महापर्व मेष व
वृषभ का गुरु, मकर का सूर्य और माध्य
मास में सम्पन्न होता है। नासिक में
सिंह राशि का गुरु, सिंह का सूर्य तथा
श्रावण मास के संयोग से पर्व होता है
इसी प्रकार उज्जैन का कुंभ सिंह राशि
का गुरु, वैशाख मास के मेष के सूर्य
में कुंभ पर्व होता है। कुंभ भारतीय
जनजीवन, संत महात्माओं के
आध्यात्मिक चिंतन, जीवन दर्शन और
प्राचीन संस्कृति का पुंजीभूत है। इसके
मांगलिक विचारधाराएं सरिताओं के
पावन जलप्रवाह के माध्यम से जन
जागृति और नवचेतना का शंखनाम
सदियों से करती आई है। बारह वष
बाद यह पुनः पुनः आ जाता है
प्रयागराज का अमृत महाकुंभ, जो
विश्व का सबसे बड़ा मेला पुनीत
पावनक गंगा जमुना, और अहश्व
सरस्वती के संगम पर उभरता एक लघु
भारत। प्रयाग की धरती से एक बार
फिर गूंज रहा है रहम एक हैरू का
अमृत घोष। अजस्र वाहिनी गंगा

जमुना-सरस्वती का संगम-स्थल भूमंडल के पूर्व यानी नासिक (प्रयाग) पर होता है राशि चक्र में कुरु राशि पर गुरुदेव बृहस्पति के परिभ्रम पर यह अमृत योग आता है। यह गौर करने की बात है कि सभ्यता एवं संस्कृति के विकासमान जीवन और जगत को प्राचीन समय में ही नहीं आज के वैज्ञानिक तकनीकी समय भी महाकुंभ से संबंधित शहरों एवं निकटवर्ती क्षेत्रों के व्यापार, व्यवसाय, विपणन, वाणिज्य को बल मिलता है। यहां वस्तुओं का राष्ट्रव्यापी विनियोग होता है। इन विराट कुंभ मेलों शास्त्रज्ञों, ज्योतिषियों, विद्वानों, कलाकारों, कवियों का समागम सम्भव होता है, तो दूसरी ओर नाम दान द्वारा अपरिग्रह की भावना को सुनिष्ठि जाती है। पर्यटन एवं पर्यावरण महत्व को आत्मसात करने वाले मानव समाज की यात्रा की प्रवृत्ति, उन एकरस जीवन से हटाकर पाप विमुक्ति तथा ग्रहचक्र एवं दुर्देव से सुरक्षा देने वाले भाव जगाता है। इस पावन-महापर्व वाले आकर्षण ही ऐसा है कि भारत कोने-कोने से और तो और विश्व अनेक देशों के लोग भी कुंभ नगरी सिमटने लगे हैं। कुंभ महापर्व की यह पराकाष्ठा ही है की उत्तरप्रदेश वर्ष सरकार ने 12 जनवरी 2025 आयोजित गंगा किनारे कुंभ स्थल क्षेत्र को कुंभ जिला घोषित कर दिया है यद्यपि इनकी भाषा, वेशभूषा, रंगदण्ड

सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, परन्तु इनका लक्ष्य एक होता है, मंजिल एक होती है सभी में एक ही भावना और समरसता के दर्शन किये जा सकते हैं और यह है अनेकता में एकता का संगम। आज का मनुष्य क्या स्त्री, पुरुष, बाल-अबाल, साधु महात्मा, धन्वान-गरीब, गृहस्थ, संन्यासी, साक्षर असाक्षर हर तरह के लोग और समुदाय, कष्टों समस्याओं की चिंता नहीं करते हुये भी अमृत कुंभ के अमृतपान के लिये सहज एवं प्रसन्नता के साथ प्रत्येक स्थिति में भी उद्यत रहते हैं, यहीं तो है इस महापर्व का महात्म्य। भारतीय लोक जीवन में मेलों का अपना एक विशेष स्थान रहा है। इस दृष्टि से यदि देखा जाय तो हम पाते हैं कि हमारे देश के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में समय-समय पर मेलों का आयोजन होता रहता है। चूंकि ऐसे प्रत्येक आयोजन के लिये कोई कारण होना जरुरी होता है। इसलिए भारत में लगने वाले अधिकांश मेले किसी उत्सव, पर्व या धार्मिक महत्व वाले दिन के अवसर पर आयोजित होते हैं। वैसे इन सभी मेलों का धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और समाज शास्त्रीय भी महत्व रहता है। लेकिन आधुनिक युग में इनके आयोजन के साथ आर्थिक पक्ष अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ इनके आयोजन में आयोजक को, सरकार हो या अन्य कोई संस्था, उसे काफी पैसा खर्च करना ही रहता है। दूसरी तरफ इन मेलों में आने वाले भी भारी खर्च करते हैं, और जो व्यापारी, उद्योगपति वा दुकानदार इनमें आते हैं वे अच्छी कमाई के साथ अपने उत्पादन या अपनी वस्तु का अच्छा प्रचार करके भविष्य में बिक्री बढ़ाने का प्रयास भी करते हैं। भारतीय मेलों का एक लम्बा इतिहास रहा है। इनमें अन्य मेलों की अपेक्षा प्रयागराज, हरिद्वार, और नासिक उज्जैन, के महाकुंभ का अपना इतिहास है। साथ ही ये आयोजन देश के विभिन्न भागों में होने वाले मेलों की तुलना में विशाल और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। इस तरह के मेले या महापर्व इन स्थानों पर-प्रतिवर्ष न होकर बारह वर्ष में एक बार आयोजित होते हैं। इस कारण भी ये अधिक बड़े और अधिक महत्वपूर्ण बन गए हैं। सामान्यतः इन चारों मेलों का धार्मिक और ज्योतिष शास्त्रीय महत्व अधिक माना गया है, लेकिन इनके सामाजिक महत्व को भी कम नहीं कहा जा सकता है। वैसे इन चारों कुंभों में साधु-महात्मा बड़ी मात्रा में आते हैं, और अपने अपने मतों का प्रचार प्रसार भी करते हैं। इस तरह कुंभ महापर्व सामाजिक जीवन के परिवर्तन और नियंत्रण की स्थितियों को समझने और उनके संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं।

दिल्ली-एनसीआर के लोग आखिर कहाँ जाएं

-३-

राजधानी दिल्ली का प्रदूषण
के स्तर तक पहुंच गया है कि
नितिन गडकरी दिल्ली आने से
गठकरी ने कहा कि स्वास्थ्य पर
बाव पड़ने से वह दिल्ली आने
में। गडकरी मंत्री हैं। उनके पास
सुविधाएं हैं। वह कहीं भी
आवागमन कर सकते हैं।
ली और राष्ट्रीय राजधानी
सेत्र (एनसीआर) के करोड़ों
वान का है। इतने लोग अपना
घर-बार छोड़ कर कहाँ जाएं।
धीमे जहर को पीना उनकी
गई है। ज्यादातर सांसदों,
अकूत दौलत है। उनके लिए
चर्चन के लिए कहीं भी देश में
पर आना-जाना आसान है।
उन्होंने को संसद और विधानसभा
वालाने की ज्यादा चिंता नहीं है।
एनसीआर के लोगों को
नरी और नेताओं के नकारात्मक
झेलने को मजबूर होना पड़े
वीर राजधानी होने के बावजूद
तरह के जानलेवा प्रदूषण की
वाहनों और फैक्टरी के धुएं से
प्रदूषण, युमुना का प्रदूषण और
से निकलने वाले कचरे का
तरह के प्रदूषण का बोझ
ए दिल्ली अभिशप हो चुकी
केंद्र में भाजपा गठबंधन की
में आप की सरकार मौजूद हैं।
दिल्ली में लंबी अवधि तक
आसन रहा है। प्रदूषण से निपटने

दिल्ली में कचरे का पहाड़ आज भी नेताओं के दावों-वादों को मुंह चिढ़ा रहा है। हिंदू मुस्लिम विवाद और भ्रष्टाचार की तरह प्रदूषण नेताओं के लिए कभी चुनावी मुद्दे नहीं बन पाया। जब कभी प्रदूषण का मुद्दा उठता भी है, तो केंद्र और दिल्ली के सरकार गेंद एक-दूसरे के पाले में डाल कर अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाती हैं। यहाँ वजह है कि दिल्ली और एनसीआर के आबोहवा इतनी बिगड़ चुकी है कि सांसालेना भी दूधर हो रहा है। विशेषज्ञों वे मुताबिक दिल्ली में रहने वाले कम से कम 10 सिपारेट जितना प्रदूषण हर दिन लेने के विवश हैं। सुरीम कोट और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जैसी सौव्याधानिक स्वतंत्र संस्थाएँ भी तमाम प्रयासों के बावजूद दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण से निपटने में प्रभावी भूमिका अदा नहीं कर सकीं। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने अपने बयान में स्वीकार किया था कि दिल्ली में 50 प्रतिशत प्रदूषण वाहनों से निकलता है। गडकरी देश के परिवहन मंत्री हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर प्रदूषण की विकाराल समस्या से निपटने के जिम्मेदार किसकी है। जब देश का परिवहन मंत्री ही समस्या के समाधान से मुहुर चुराने लगे तो अवाम किसीसे उम्मीद करे। स्विस संगठन की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दिल्ली को सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला राजधानी शहर बताया गया है। रिपोर्ट 2023 के अनुसार, 2023 में 134 देशों में से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद भारत की वायु गुणवत्ता तीसरी सबसे खराब की भविष्यवाणी की गई। राष्ट्रीय राजधानी को वर्ष 2018 से लगातार

कहा गया कि 6 अरब लोग गुपचर करते हैं, (डब्ल्यूएचओ) निर्देश स्तर 5 में अधिक है। उष्ण से खराब ए सुप्रीम कोर्ट नकारापन के सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम क दैरान कहा र्ट में चौकाने देता है। अदालत ने और दिल्ली कमी है। साथ में फिलहाल ली सरकार, एम और अन्य की पूरी तरह भ्रष्ट करने की आयोग पर करने के लिए इंद्र सरकार के लागू करने में हुआ है जब गुणवत्ता बहुत सांस सबधी है। मामले की तरफ की पीठ ने द्वारा खेतों में गासों को मात्र खराब होने का एक स्पष्ट कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्यों में पराली जलाने की बार-बार होने वाली घटनाएँ हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 23 अक्टूबर को पर्यावरण कानूनों को शक्तिहीन बनाने के लिए केंद्र की आलोचना की और कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएस्यूएम) अधिनियम के तहत पराली जलाने पर डंड से संबंधित प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है। मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के प्रावधान को लागू करने के लिए कोई आवश्यक तंत्र बनाए बिना ही अधिनियम लागू कर दिया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसार भारत में हर साल पैदा होने वाले 22 मिलियन टन चावल के ठूंठ में से लगभग 14 मिलियन टन पराली का आग के हवाले कर दिया जाता है। यह पैदा होने वाले चावल के ठूंठ का लगभग 63.6 प्रतिशत है और हरियाणा और पंजाब में अकेले जलाई जाने वाली पराली का 48 प्रतिशत हिस्सा है। हालत यह है कि बोटों के डर से राज्य और केंद्र की सरकारें पराली जलाने पर पूरी तरह रोक नहीं लगा पा रही हैं। राजनीतिक दलों के लिए किसानों का बोट बैंक आम लोगों के जीवन पर भारी पड़ रहा है। यही वजह है कि पराली जलाने की हर साल होने वाली घटनाओं के बावजूद कोई भी सरकार सख्त कदम उठाने से हिचकिचाती है। यहां तक कि सरकां बोटों के लालच में लगातार अदालत के निर्देशों की अवहेलना कर रही हैं। कुछ दिन पहले हरियाणा सरकार ने कथित तौर पर कैथल किसानों को गिरावंश गतिविधियों पर लालच के कारण राज्य वे 24 अधिकारियों का था। गैरतलब है कि हर साल जलाते हैं इसके बावजू पिरफ्टारी महज दिन 2022 में पंजाब, हरियाणा दिल्ली एनसीआर के इन-सीट प्रबंधन को बढ़ावा देने की ओर पराली जलाने के लिए 2018-22 के तहत 1387.6 करोड़ मिले।

राष्ट्रीय हरित 22 अक्टूबर को दिया कि वह बता पराली जलाने पर क्या कदम उठाए एनजीटी के लगभग प्रदूषण से बिगड़े नहीं हुआ है। दरअसल के इशारों पर कारण कारण किसानों के कारण करने से कतराते विश्व में प्रदूषण के राजधानी के हाल तक अदालतें नौकरी कार्रवाई नहीं करेंगी में सुधार संभव न होती सांसों को स्व

तार किया था। ऐसी मलगाने में विफल रहने कृषि विभाग के करीब निलंबित भी किया गया हजारों किसान पराली कुछ किसानों की बाबा है। केंद्र सरकार ने रेयाणा, उत्तर प्रदेश और योजने में फसल अवशेषों के लिए कृषि यंत्रीकरण योजना शुरू की। पंजाब ने समस्या से निपटने के दौरान इस योजना के रोड रूपए से अधिक अधिकरण (एनजीटी) ने जाव सरकार को निर्देश दिया कि राज्य में धान की फसल लगाने के लिए उसने बाजार प्रयासों के बावजूद डालात में ज्यादा सुधार नहीं करते हैं। नेता वोट के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। यह निश्चित है कि लेकर बदनाम हो चुकी है। सुधारने के लिए जब शाहों के खिलाफ कठोर, तब तक इनकी प्रवृत्ति नहीं है। दिल्ली की गंदी छ बनाए की जरूरत है। (स्वतंत्र लेखक)

भारतीय कृषि के भविष्य को आकार देने की आवश्यकता

-निमिषा सिंह-

आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की पाँच सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारतीय सेना विश्व की सबसे ताकतवर सेनाओं में सम्मिलित है। विश्व के सफलतम अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शामिल है। अन्य क्षेत्रों में भी भारत नियमित रूप से विकास की नई बुलंदियां छू रहा है बावजूद इसके भारत में एक क्षेत्र ऐसा भी है जो आज भी विकास की दौड़ में कहीं पीछे रह गया है। खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कृषि क्षेत्र आज भी उस स्थिति में नहीं पहुँच पाया है जिसे संतोषजनक माना जा सके। इसका परिणाम यह हुआ है कि कृषि पर निर्भर देश के करोड़ों लोग आज भी बेहद अभावों में जीवन जीने को विवश हैं और कई बार ये कृषि के माध्यम से अपनी बुनियादी जरूरतें भी नहीं पूरी कर पाते हैं।

किसान समुदाय को सशक्त बनाने नवाचारों का अन्वेषण और भारतीय कृषि के भविष्य को आकार

देने के लिए तेलंगाना की राजधानी हैंदराबाद स्थित फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैंबर एंड कॉर्पस में दो दिवसीय राष्ट्रीय किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। जिसमें कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से व्यावहारिक चर्चा करने के लिए देश भर से किसान नेता, कृषि वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रगतिशील किसान एक मंच पर एकत्रित हुए। सिफा के संस्थापक और मुख्य सलाहकार पी. चंगल रेड्डी के अनुसार भारत में खाद्य सुरक्षा और इस क्षेत्र में वैश्विक निर्यातक बनने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति के अवसर हैं। आज जलवायु परिवर्तन को ध्यान रखकर खेती करने और युवा प्रतिभाओं को खेती की ओर आकर्षित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण और कृषि निर्यात के क्षेत्रों में भी अपार अवसरों की उपलब्धता है, जिन्हें सही ढंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

भारतीय किसान संघ परिसंघ के मौजूदा चेयरमैन रघुनाथ दादा पाटील ने देश भर से आए किसान नेताओं और प्रतिनिधियों से कहा कि इसमें कोई शक नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था की ओर किसान इसकी जीवनविधि किसान सबसे बड़ा उत्पाद उपभोक्ता दोनों है। किसान वैज्ञानिकों के बीच अंतर विद्युत लिए 'प्रयोगशाला' को जोड़ने के प्रयासों की भूमिका आवश्यकता है ताकि वह इसका किया जा सके कि अत अनुसंधान जीवीनी स्तर तक कृषि में विविधता लाने के लिए किसानों को गेहूं और धान पारंपरिक फसलों के समान अनुसंधान जीवीनी स्तर तक कृषि के लिए नीतिगत पहल योजनाओं, निर्यात नीति पर चर्चा की गई। पीजेट ने एसोसिएशन के चेयरमैन बालियान ने कहा कि भारत ने 2018 में एसेसिल वैकल्पिक एकट की पावर को एकट करते हुए चीनी का न्यूनतम मूल्य तय किया था। ठीक उसी केंद्र सरकार 23 फसलों पर एसेसिल कमोडिटी एकट की

कृषि विकास के लिए जैसी सरकारी और नियंत्रित व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। इसके अलावा, व्यापक व्यवस्था के लिए व्यापक समर्थन की ज़रूरत है। इसके लिए, सरकारी और नियंत्रित व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। इसके लिए, सरकारी और नियंत्रित व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है।

जीवन और
प्रकार की रक्षा
पूर्व, नीलगाय
र हमला करने
लिए मुख्य
अपनी शक्तियों
सकता है, जो
को एक निश्चित
पर जानवरों को
ना सकता है।
गोर्गोइजेशन से
पशेषज्ञ गणधर्म
ताया कि किस
उनके सहकर्मी
चेंगल रेड़ी के
और लगातार
बाद हाल ही
ने हाई टेंशन
लिए मानक
की की है। टाकर
मूल्य का 200
दिया जाएगा।
ड-लेवल लेग
एक अतिरिक्त
र स्थान टाकर
में जाना जाता
अनुसार, जिला
नस्टट या डिप्टी
वजे के लिए

अंतिम अधिकार दिया जाएगा।
मुआवजे पर निर्णय लेने से पहले,
हम अनुरोध करेंगे कि जिला
कलेक्टर नवीनतम (14 जून
2024 को बिजली मंत्रालय के
दिशा-निर्देश) दिशा-निर्देशों पर
विचार करें। दूसरे दिन के अंतिम
सत्र में सिफा के मुख्य सलाहकार
पी. चेंगल रेड़ी के मार्गदर्शन में
सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा सिफा की
नई संगठन कार्यकारी समिति और
प्रशासनिक टीम का गठन किया
गया। महाराष्ट्र से रघुनाथ दादा
पाटील को चेयरमैन और गुजरात के
विधिन चंद्र पटेल को राष्ट्रीय
अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई वहीं
झारखंड दुमका से ताल्लुक रखने
वाली सुष्मिता सोरेन, उत्तर प्रदेश से
अशोक बालियान और तेलंगाना से
मारा गंगा रेड़ी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
का पद भार सौंपा गया। राष्ट्रीय
किसान सम्मेलन में भागीदारी
सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक से
शकर नारायण रेड़ी, गुजरात से
विधिन भाई पटेल, तमिलनाडु से
आर व्ही गिरी, आंध्र प्रदेश से कोटी
रेड़ी नरेंद्र बाबू, तेलंगाना से गोपाळ
रेड़ी, निमू वसंता, माधव रेड़ी,
सोमशेखर राव, उत्तर प्रदेश से

